

जोखिम

भय भूत एवम् भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्षरत निर्भीक राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

वर्ष : 16 अंक : 319

देहरादून गुरुवार 12 फरवरी 2026

मूल्य : ₹ 2

पृष्ठ : 8

मुख्यमंत्री ने की राज्य में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं की समीक्षा

- एस्केप टनल को समानांतर सड़कों (पैरेलल रोड्स) के रूप में किया जाए विकसित : मुख्यमंत्री
- कर्णप्रयाग से बागेश्वर तक रेल लाइन के विस्तार की संभावना पर हो कार्य
- टनकपुर - बागेश्वर रेललाइन परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने पर केंद्र सरकार से किया जायेगा आग्रह
निर्माणाधीन रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्र का होगा पुनर्विकास

देहरादून संवाददाता. राज्य में प्रस्तावित रेल परियोजनाओं में टनल के साथ बनने वाले एस्केप टनल को समानांतर सड़कों (पैरेलल रोड्स) के रूप में विकसित किया जा सके, इसकी व्यवस्था बनाई जाए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना में बनी एस्केप टनल का भविष्य में किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है, इसपर भी कार्य योजना तैयार जाए साथ ही कर्णप्रयाग से बागेश्वर तक रेल लाइन के विस्तार की संभावना पर भी कार्य किया जाए। प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में राज्य में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित रेल परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। मुख्यमंत्री

तिब्बती मार्केट में सरराह युवक की गोली मारकर हत्या

देहरादून संवाददाता. देहरादून के प्रसिद्ध तिब्बती मार्केट में एक युवक की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सुबह करीब 10:30 बजे की है जब युवक पाइन्सपल खरीद कर पैदल ही वापस जीप की तरफ लौट रहा था। मृतक टेनिस खेलने के लिए परेड ग्राउंड में आया हुआ था। परेड ग्राउंड के बाहर पाइन्सपल खरीद कर पैदल चल ही रहा था कि दो बाइक सवारों ने गोली मार दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को दून अस्पताल पहुंचाया। गोली दिल के पास लगने से डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया गया। शव को मोर्चरी में रखा गया है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार सीओ सिटी और कई थानों की पुलिस फोर्स सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।



ने अधिकारियों को टनकपुर - बागेश्वर रेल लाइन परियोजना पर भी तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा उक्त परियोजना के अंतर्गत विभिन्न वैकल्पिक मार्गों पर भी विचार किया जाए। उन्होंने कहा परियोजना के निर्माण कार्य से अधिकांश क्षेत्र एवं जनता लाभान्वित हो सके इसके लिए अल्मोड़ा एवं सोमेश्वर क्षेत्र को भी जोड़ने की संभावनाओं पर कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार से टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने का आग्रह किया जाए, जिससे इसके निर्माण कार्य को गति मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित रेलवे स्टेशनों के लिए इंटिग्रेटेड प्लान बनाया जाए जिससे इन रेलवे स्टेशनों के आसपास स्थानीय लोगों के लिए बाजार विकसित हो सके। उन्होंने कहा सभी निर्माणाधीन रेलवे स्टेशनों में स्वयं सहायता समूहों, राज्य की स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्तावित रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में अभी से लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए उन्हें होमस्टे एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे

में जन जागरूकता पर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माणाधीन रेलवे स्टेशनों के आसपास स्थित विभिन्न गांव, कस्बों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी रोड मैप तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित रेलवे स्टेशनों के आसपास के स्थानों का समुचित पुनर्विकास किया जाए। ताकि रेल परियोजनाओं के निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भविष्य में बड़ी संख्या में उत्तराखंड आने वाले लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाया जाए। बैठक में बताया गया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत 72.5 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है साथ ही टनल निर्माण का 95.30% कार्य पूरा हो गया है। इस परियोजना के अंतर्गत कुछ कल 28 टनलों का निर्माण किया है जिनमें से 16 मुख्य टनल एवं 12 एस्केप टनल हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रस्तावित रेलवे स्टेशनों का निर्माण अलग-अलग थीम के आधार पर किया जा रहा है। जिसमें शिवपुरी स्टेशन को नीलकण्ठ महादेव, ब्यासी को महर्षि वेदव्यास, देवप्रयाग को समुद्र मंथन, जनासु को उत्तराखंड कल्चर, मलेथा को वीर माधो सिंह भंडारी, श्रीनगर को मां राज राजेश्वरी देवी, चोलतीर को पांच महादेव, राधा कृष्ण थीम पर आधारित निर्माण किया जा रहा है।

सूबे में शैक्षणिक संवर्ग का बनेगा त्रि-स्तरीय ढांचा: डॉ. धन सिंह रावत

- डायटों में रिक्त पदों पर होगी स्थाई नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति पर तैनात शिक्षक होंगे वापस
- कहा, नये शिक्षण सत्र से पहले विद्यालयों में उपलब्ध हो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें

देहरादून संवाददाता. विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत शैक्षणिक संवर्ग का नया त्रि-स्तरीय ढांचा बनाया जायेगा। जिसका प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट में लाया जायेगा। इसके अतिरिक्त डायटों में रिक्त प्रवक्ता संवर्ग के 222 रिक्त पदों को भरने के लिये अध्यायन लोक सेवा आयोग को भेजा जायेगा ताकि उक्त पदों पर स्थाई नियुक्ति की जा सके। नये शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पूर्व प्रदेशभर के सभी विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी जायेगी। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज शासकीय आवास पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने केन्द्रीय विद्यालयों की भांति प्रदेश में शिक्षकों के त्रि-स्तरीय ढांचे के गठन में देरी पर विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। साथ ही सभी जनपदों के डायटों में लम्बे समय से रिक्त चल रहे प्रवक्ता संवर्ग के 222 पदों को भरने के लिये अध्यायन लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिये ताकि उक्त पदों के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति पर तैनात प्रवक्ताओं को उनके मूल विभाग में वापस भेजा जा सके। विभागीय मंत्री ने अधि कारियों को सख्त निर्देश दिये कि नये शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले सभी विद्यालयों में सरकार द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जायें। यदि किसी विद्यालय में समय पर पुस्तकें उपलब्ध नहीं होंगी तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने एससीआईआरटी के ढांचे के गठन एवं नियमावली बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये।

संक्षिप्त समाचार...

पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुण्यतिथि पर किया याद

देहरादून संवाददाता. महानगर भाजपा कार्यालय में बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को सेवा समर्पण कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन करते हुए कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा बताए मार्ग पर चल रही है। उनका भारतीय चिंतन बड़ा विस्तार पूर्ण रहा। मुख्य अतिथि पार्टी महामंत्री कुंदन परिहार वे महान चिंतक दार्शनिक व राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। मुख्य वक्ता ज्योति प्रसाद गैरीला ने कहा कि उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया।

सुराज सेवा दल ने नगर निगम के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन

देहरादून संवाददाता. सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को नगर निगम में धरना प्रदर्शन दिया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम अतिक्रमण हटाने के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहा है। वक्ताओं ने कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। लेकिन निगम कार्रवाई के नाम पर गरीबों का उत्पीड़न कर रहा है। इस दौरान सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी, प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र पाल सिंह आदि मौजूद रहे।

दून में आज से शुरू होगा द्रोणा महोत्सव

देहरादून संवाददाता. राजधानी के आईटी पार्क रोड स्थित सहस्रधारा मार्ग पर गुरुवार से 10 दिवसीय द्रोणा महोत्सव 2026 शुरू होगा। भारतीय ग्रामोत्थान संस्था की ओर से आयोजित इस महोत्सव में उत्तराखंड की पारंपरिक हस्तशिल्प, कला और स्थानीय उत्पादों को झलक देखने को मिलेगी।

सम्पादकीय

भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए नुकसान का पहलू

अमेरिका में टैरिफ 18 प्रतिशत होने से भारत के श्रम-केंद्रित उद्योगों को राहत मिलेगी। लेकिन अमेरिका की भू-राजनीतिक रणनीतियों से जुड़ी शर्तें डील में शामिल हुईं, तो आर्थिक के साथ-साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए भी वो हानिकारक बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद डॉनल्ड ट्रंप ने अपने चिन्तन-परिचित अंदाज में भारत से ट्रेड डील होने का एलान किया। कहा कि इसके तहत अमेरिका भारत पर श्लिबेशन डे टैरिफ को 25 से घटा कर 18 प्रतिशत कर देगा। बदले में भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करेगा, अमेरिका से व्यापार में टैरिफ एवं गैर-टैरिफ रूकावटों को शून्य कर देगा, और 500 बिलियन डॉलर के ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला एवं अन्य उत्पाद खरीदेगा। 500 बिलियन डॉलर का अर्थ भारत के सालाना बजट का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा (तकरीबन 46 लाख करोड़ रुपये) है। बहरहाल, ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जारी अपने बयान में प्रधानमंत्री ने सिर्फ यह उल्लेख किया कि भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में अब सिर्फ 18 प्रतिशत आयात शुल्क लगेगा। इससे ट्रेड डील को लेकर फिर से अस्पष्टता बन गई। बहरहाल, यह साफ है कि इस डील को हासिल करने के लिए भारत ने आगे बढ़ कर कई बड़ी रियायतें दी हैं। उनमें से कई तो करार के पहले ही दे दी गईं। इनमें अमेरिका के कृषि, वाहन, सौंदर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, धातु एवं केमिकल्स उत्पादों पर भारत में आयात शुल्क में भारी कटौती शामिल है। साथ ही रक्षा सौदों का दायरा बढ़ाया गया। परमाणु उत्तरदायित्व कानून में अमेरिकी कंपनियों के अनुकूल बदलाव किया गया। ट्रंप प्रशासन के दबाव में भारत ने रूस से तेल की खरीदारी घटाई, ऐसी खबरें सुर्खियों में रही हैं। अब अगर ये पहलू ट्रेड डील का हिस्सा है, तो यह बेहद आपत्तिजनक बात होगी। इसलिए कि यह अपने संप्रभु निर्णय को किसी अन्य देश की भू-राजनीतिक जरूरतों के सामने समर्पित करने जैसा होगा। दरअसल, खरीदारियों के बारे में भी कोई व्यक्ति या देश अपनी जरूरत एवं बाजार के तर्कों से फैसला लेता है। किसी दबाव में आकर इस बारे में बंधना अपने हितों से समझौता होगा। अमेरिका में टैरिफ 18 प्रतिशत होने से स्वयं, जेवरात आदि जैसे श्रम-केंद्रित उद्योगों को राहत अवश्य मिलेगी। लेकिन अमेरिका की भू-राजनीतिक रणनीतियों से जुड़ी शर्तें ट्रेड डील में शामिल हुईं, तो आर्थिक के साथ-साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए भी वो नुकसान का पहलू होगा।

धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर

देहरादून संवाददाता. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को देहरादून स्थित सचिवालय में हुई बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। इनमें सबसे अहम मुद्दे कैबिनेट में बोनस एक्ट, ईएसआई में डॉक्टर्स के पदों पर मंजूरी, कारागार एक्ट में संशोधन, सूक्ष्म खाद्य योजना और वन विभाग के केंद्रित कर्मियों को न्यूनतम मानदेय से संबंधित हैं। राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद उत्तराखंड में ड्रग फ्री मुहिम और तेज होगी। अभी तक एंटी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स में पुलिस फोर्स से प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई लिए जा रहे थे। टॉस्क फोर्स का गठन 2022 में किया गया था। अब इस फोर्स के लिए अलग से ढांचा खड़ा करने की शुरुआत हुई है। इस क्रम में राज्य मुख्यालय में पहली बार 22 पदों का सृजन किया गया है। एक पुलिस उपाधीक्षक, दो ड्रग निरीक्षक, एक निरीक्षक, दो उपनिरीक्षक, चार मुख्य आरक्षी और आठ आरक्षी, दो आरक्षी चालक समेत कुल 22 पद सृजित किए जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने वन विभाग में कार्यरत दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान दिए जाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने सरकार को संस्तुति दी थी। इस आधार पर सरकार ने 589 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को न्यूनतम 18 हजार रुपये वेतन देने का निर्णय लिया है। वन विभाग/वन विकास निगम में कार्यरत दैनिक श्रमिकों की कुल संख्या 893 है, जिसमें से 304 श्रमिकों को पूर्व से ही न्यूनतम वेतनमान का लाभ प्राप्त हो रहा है। 13 राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) के अंतर्गत चिकित्सा सेवा सवार्गों के चिकित्सा अधिकारियों और उच्चतर पदों की सेवा-शर्तों के निर्धारण के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस क्रम में उत्तराखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली, 2026 को प्रख्यापित किया गया है, जिसके तहत कुल 94 पद होंगे। इनमें 76 चिकित्सा अधिकारी, 11 सहायक निदेशक, छह संयुक्त निदेशक और एक अपर निदेशक का पद शामिल है। इससे पहले, ईएसआई के ढांचे में एक सीएमओ और 13 चिकित्सा अधिकारी के पद शामिल थे। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की कार्यान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक विस्तारित किए जाने के संबंध में

भी राज्य मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की कार्यान्वयन अवधि को एक वर्ष के लिए 31 मार्च 2026 (वित्तीय वर्ष 2025-26) तक बढ़ाया गया है। इस क्रम में राज्य सेक्टर के अंतर्गत संचालित "मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की कार्यान्वयन अवधि को भी वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 31 मार्च 2026) तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में यदि भारत सरकार के स्तर पर इस योजना की अवधि विस्तारित होती है, तो राज्य में भी इस विस्तारित माना जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड कारागार और सुध रात्मक सेवाएं (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारूपण के संबंध में भी निर्णय लिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों में यह निर्देशित किया गया है कि कारागार नियमावली/मॉडल प्रिजन मैनुअल में प्रयुक्त "आदतन अपराधी (इंफ्रजंजनस वॉर्मिदकमते)" शब्द की परिभाषा संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों के अनुरूप होनी चाहिए। संशोधन विधेयक को आगामी सत्र में माननीय उत्तराखंड विधान सभा के समक्ष पुनः स्थापित किए जाने की राज्य मंत्रिमंडल ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है। 6. कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान उद्योगों को राहत प्रदान किए जाने के उद्देश्य से बोनस संदाय (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि नियोजक के पास आवंटनीय अधिशेष (एसवबइसम नैतचसने) उपलब्ध होने की स्थिति में ही कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस का भुगतान किया जाएगा। उक्त विधेयक में किए गए प्रावधानों के संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा असहमति व्यक्त की गई। साथ ही वर्तमान में कोविड-19 महामारी जैसी परिस्थितियाँ विद्यमान न होने तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराए जाने के कारण विधेयक को आगे बढ़ाया जाना संभव नहीं हो पाया।

त्वरित विकास को समर्पित कल्याणकारी केन्द्रीय बजट

डॉ. महेन्द्र सिंह

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए संसद में पेश किया गया बजट देश के त्वरित विकास को समर्पित कल्याणकारी बजट है। इस बजट में समाहित प्रस्तावों में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने और उसे निरन्तर बनाये रखने पर जोर दिया गया है। साथ ही, लोककल्याण के लिए बजट प्रस्तावों पर भी पर्याप्त बल दिया गया है। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में तीन कर्तव्यों को उजागर किया। ये हैं : () अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के प्रति लचीलेपन में वृद्धि करते हुए आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे बनाये रखना; जन आकांक्षाओं की पूर्ति और उनकी क्षमताओं का वर्द्धन करना एवं देश के प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और वर्ग तक संसाधनों, सुविधाओं तथा अवसरों को पहुंच को सुनिश्चित करना। इस तरह ये कर्तव्य मोदी सरकार की सर्वसमावेशी एवं पोषणीय विकास की रणनीति को सुस्पष्ट रूप में परिभाषित करते हैं। ध्यातव्य है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के केन्द्र में एक ओर आर्थिक संवृद्धि की गति को तेज करना रहा है वहीं दूसरी तरफ सापेक्षता वचित लोगों एवं क्षेत्रों को उनकी क्षमता व सामर्थ्य को बढ़ाते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल करना रहा है। इस दृष्टि से यह कहना समीचीन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास का ध्येय वाक्य लोकनीतियों के प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन का नाभिकेन्द्र रहा है। इसमें आर्थिक समृद्धि एवं लोककल्याण में वृद्धि स्वतः विहित रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा सर्वव्यापक आर्थिक सुधारों का मूल विचार रिकार्म, परफार्म व ट्रांसफार्म रहा है। इस बजट में भी, बजट प्रावधानों को अधिक परिणामोन्मुखी बनाने के लिए सुधारों के क्रम को जारी रखा गया है। विकसित भारत के महालक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस बजट में कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र, एएसएमई, ओडीओपी, रिन्यूबल व न्यूक्लियर एनर्जी, सेमिकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलमार्ग व रेल विकास, डिजिटल इंडियन, निर्यात संवर्द्धन, रक्षा क्षेत्र इत्यादि संभावनापूर्ण क्षेत्रों एवं तत्सम्बन्धी क्रियाओं के संवर्द्धन व विकास के लिए वित्तमंत्री द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित आवंटन किए गये हैं। साथ ही, मानव पूँजी के निर्माण से सम्बन्धित क्षेत्रों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, युवा और दिव्यांग सशक्तिकरण पर पर्याप्त बल दिया गया है। वस्तुतः मानव पूँजी के बेहतर विकास से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा जनकल्याण में वृद्धि होगी। वित्तमंत्री ने इस बजट में राजकोषीय सुदृढीकरण को जारी रखते हुए इस पर विशेष बल दिया है। हाल के वर्षों में जीडीपी के सापेक्ष राजकोषीय घाटा में निरन्तर गिरावट से इस बात की पुष्टि होती है कि मोदी सरकार का राजकोषीय प्रबन्धन सम्बन्धी निष्पादन श्लाघनीय रहा है। वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.7 प्रतिशत; 2022-24 में 6.5 प्रतिशत 2023-24 में 5.5 प्रतिशत; 2024-25 में 4.8 प्रतिशत एवं 2025-26 में 4.4 प्रतिशत था। इसे 2026-27 के बजट में कम करके 4.3 प्रतिशत पर रख गया है। ये प्रवृत्तियाँ राजकोषीय व्यवस्था को मजबूती की परिचायक हैं। मोदी सरकार की राजकोषीय प्रवीणता एवं बेहतर वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम है कि जीडीपी के सापेक्ष राजकोषीय घाटा निरन्तर घटा है। साथ ही, वित्तमंत्री इस बात में भी सफल रही हैं कि उन्होंने इस बजट में जीडीपी के सापेक्ष केन्द्र सरकार के ऋण को 55.6 प्रतिशत पर रखा है। यह वर्ष 2025-26 के लिए 56.1 प्रतिशत रखा गया था। साथ ही, इस बजट में जीडीपी के सापेक्ष राजस्व घाटा एवं प्राथमिक घाटा में भी कमी आई है। घटते घाटे एवं ऋण से निजी पूँजी निवेश में वृद्धि होगी। इस बजट में, राजस्व में सतत वृद्धि; पूँजीगत व्यय में वृद्धि और राजकोषीय पारदर्शिता में सुधार के संकेतकों से भी देश की राजकोषीय सुदृढता की पुष्टि होती है। पूँजीगत खर्च के जरिये अवस्थापना क्षेत्र के विकास न विकास को तेज करने और रोजगार को बढ़ाने में उल्लेखनीय तौर पर योगदान दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक विकास में धमनियों का कार्य करता है। इसलिए यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी सरकार द्वारा किया गया निवेश लगातार विकास का इंजन बना हुआ है। एक ओर जहाँ केन्द्र सरकार स्वयं पूँजीगत व्यय को बढ़ा रही है; वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारों को भी अनुदान व ऋण देकर उनके पूँजीगत खर्च को बढ़ाने में मदद कर रही है। वर्ष 2025-26 की तुलना में 2026-27 को बजट में पूँजीगत आवंटन में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि राज्यों को दी जाने वाली अनुदान राशि को भी जोड़ लिया जाय तब प्रभावी पूँजीगत व्यय की वृद्धि 22 प्रतिशत बैठती है।

आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने किया नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का औचक निरीक्षण, बायोमेट्रिक उपस्थिति एवं अनुशासन पर सख्ती

देहरादून संवाददाता. आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने आज देहरादून के बसंत विहार स्थित नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का औचक निरीक्षण कर विभागीय कार्यप्रणाली का व्यापक आकलन किया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने विभिन्न शाखाओं में चल रहे कार्यों की प्रगति, फाइल निस्तारण की स्थिति, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा की तथा अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं उत्तरदायी कार्य संस्कृति अपनाने के निर्देश दिए। सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप विकास कार्यों में गति और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करते हुए जनहित से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। बागेश्वर एवं गरुड़ जीआईएस आधारित महायोजना की समीक्षा निरीक्षण के उपरांत डॉ. आर. राजेश कुमार ने बागेश्वर एवं गरुड़ की जीआईएस आधारित महायोजना (मास्टर प्लान) की समीक्षा बैठक में सहभागिता की। बैठक में बागेश्वर जनपद के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों सहित जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान महायोजना के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। नगरीय विस्तार, यातायात प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधाओं एवं आधारभूत



संरचना विकास से संबंधित बिंदुओं पर गहन विचार-विमर्श हुआ। सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने निर्देश दिए कि महायोजना को स्थानीय आवश्यकताओं, भौगोलिक परिस्थितियों एवं भविष्य की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया जाए, ताकि योजनाबद्ध और सतत विकास सुनिश्चित हो सके। 1.0 की प्रगति पर जोर: सचिव महोदय द्वारा के अंतर्गत संचालित कार्यों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरलीकरण एवं विनियमन शिथिलीकरण से संबंधित कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए, जिससे निवेश प्रोत्साहन एवं ईज ऑफ

ड्रिंग बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी एवं डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाना समय की आवश्यकता है। बायोमेट्रिक उपस्थिति एवं अनुशासन पर सख्ती: निरीक्षण के दौरान सचिव महोदय ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से बायोमेट्रिक उपस्थिति का विवरण प्राप्त किया तथा अनुपस्थित कार्मिकों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना अनुमति अथवा अनुचित कारण के किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिना अनुमति अनुपस्थित कार्मिकों को स्पष्टीकरण

जारी करने के निर्देश भी प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि कार्यालयीन अनुशासन एवं समयपालन विभागीय कार्यकुशलता की आधारशिला है और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। निरीक्षण के समय उपस्थित राजपत्रित अधिकारियों में बालेश्वर मुख्तल (सहायक अधिकारी), संजिव कौशिक (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी), श्रद्धा बहुगुण्टी, रूबी, प्रीति सैनी, हिमाशु कुमार, हरीश शर्मा (सहायक नियोजक) तथा कु. अंजली डंगवाल (सहायक वास्तुविद नियोजक) शामिल रहे। निवेश और विकास को गति दी जाएगी - डॉ. आर. राजेश कुमार: राज्य के संतुलित एवं सुनियोजित विकास के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास है कि सभी महायोजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं, पर्यावरणीय संतुलन और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की जाएं। विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निवेश और विकास को गति दी जाएगी। साथ ही, कार्यालयीन अनुशासन एवं कार्य संस्कृति को सुदृढ़ करना भी आवश्यक है, ताकि जनता को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं प्रदान की जा सकें। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा है कि वे टीम भावना के साथ कार्य करते हुए उत्तराखण्ड के समग्र विकास में योगदान दें।

एनएचएम के तहत केन्द्र सरकार को भेजी जायेगी एक हजार करोड़ की पीआईपी

- विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ की मंत्रणा

- कहा, कार्ययोजना में नवीन योजनाओं को भी करें शामिल

देहरादून संवाददाता. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढीकरण एवं संवर्धन के लिये केन्द्र सरकार को वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु करीब एक हजार करोड़ की प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान (पीआईपी) भेजी जायेगी। जिसमें राज्य की वर्तमान आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये आधा दर्जन नई योजनाओं को भी शामिल किया जायेगा। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु केन्द्र सरकार को भेजी जाने वाली पीआईपी को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। जिसमें उन्होंने एनएचएम के अंतर्गत पूर्व से संचालित कार्यक्रमों के के आलावा आशाओं का मानदेय बढ़ाये जाने, वैक्सिन स्टोरेज हेतु आवश्यक उपकरण, कोल्ड चेन उपकरण, मॉडल इम्युनाइजेशन सेंटर की स्थापना, चारधाम हेतु मोबाइल वैक्सिनेशन वैन, पर्वतीय क्षेत्रों में सेफ्टी पिट्स व वीपीडी सर्विलांस आदि को प्रमुखता से पीआईपी में शामिल करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। इसके अलावा उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढीकरण के लिये राज्य के सभी सांसदगणों से भी सुझाव आमंत्रित कर पीआईपी में शामिल करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के कुछ विकासखण्डों का चयन कर मोतियाबिंद संभावित रोगियों की शतप्रतिशत जांच करने के निर्देश भी बैठक में दिये। डॉ. रावत ने प्रत्येक ब्लॉकों में चिकित्सकों के लिये आवश्यकतानुसार ट्रांजिट हॉस्पिट के निर्माण, वृहद स्तर पर टीकाकरण अभियान का संचालन के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर मिशन निर्देशक एनएचएम मनुज गोयल ने बताया कि राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार पीआईपी तैयार कर शीघ्र केन्द्र सरकार को भेजी दी जायेगी। जिसमें प्रदेश के सांसदगणों को सुझावों को भी शामिल किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने किया गाय संरक्षण पर आधारित फिल्म 'गौदान' का अवलोकन

देहरादून संवाददाता. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून स्थित सेंट्रियो मॉल, हाथीबडकला में किया। इस अवसर पर उन्होंने फिल्म की विषयवस्तु को भारतीय संस्कृति, ग्राम्य जीवन और गौ-संवर्धन को परंपरा से जुड़ा अत्यंत सार्थक एवं प्रेरणादायी प्रयास बताया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौ माता को विशेष स्थान

प्राप्त है। गाय केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि, पोषण एवं पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला भी है। 'गौदान' जैसी फिल्में समाज में गौ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आधारित इस फिल्म को राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में टैक्स फ्री किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस फिल्म को देख सकें और गौ संरक्षण के प्रति जागरूकता का व्यापक प्रसार हो सके। उन्होंने कहा कि यह निर्णय समाज में सकारात्मक संदेश देने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में गौशालाओं के सुदृढीकरण, निराश्रित गोवंश के संरक्षण, पशुपालकों को प्रोत्साहन तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि गौ आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए। फिल्म के निर्माता विनोद कुमार चौधरी सहित पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की पावन भूमि कला, साहित्य और संस्कृति की समृद्ध धरोहर रही है। राज्य सरकार उत्तराखण्ड को फिल्म निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रभावी फिल्म नीति लागू की गई है, जिसके अंतर्गत फिल्म निर्माताओं को आकर्षक सब्सिडी, सिंगल विंडो क्लीयरेंस, शूटिंग हेतु सरल अनुमति प्रक्रिया तथा स्थानीय कलाकारों एवं तकनीशियनों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। नई फिल्म नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और राज्य में फिल्मों का गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक वातावरण, पर्वतीय संस्कृति एवं विविध लोकेशन फिल्मांकन के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। सरकार का उद्देश्य है कि अधिकाधिक फिल्में प्रदेश में शूट हों, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हों और पर्यटन को भी नई गति मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा फिल्म विकास परिषद को सशक्त किया गया है तथा फिल्म स्टूडियो एवं आधारभूत संरचना के विकास की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है।



चमियाला-घनसाली के बीच मार्च से शुरू होगी पहली सिटी बस सेवा

नई टिहरी संवाददाता. नगर पंचायत चमियाला क्षेत्र के लोगों के लिए खुशखबरी है। आगामी मार्च से नगर पंचायत पहली बार सिटी बस सेवा शुरू करने जा रही है। सिटी बस सेवा शुरू होने से चमियाला से रोजाना घनसाली आने-जाने वाले कर्मचारियों, स्थानीय लोगों और बालगंगा महाविद्यालय संदुल के छात्र-छात्राओं को आवागमन की सुविधा मिलेगी। नगर पंचायत बोर्ड के गठन का एक वर्ष पूरा होने पर चमियाला में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में नगर पंचायत की ओर से कई नई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। लंबे समय से परिकल्पित सुविधा के अभाव से जूझ रहे क्षेत्रवासियों को अब सिटी बस सेवा की सौगात मिलने जा रही है। घनसाली से चमियाला के बीच नियमित सिटी बस संचालन की तैयारी शुरू हो गई है। आगामी मार्च से इसे शुरू करने की योजना है। नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद सिंह राणा ने बताया कि सिटी बस सेवा के लिए विधायक शक्ति लाल शाह ने विधायक निधि से धनराशि की स्वीकृति दी है। सिटी बस योजना चमियाला से घनसाली तक संचालित की जाएगी। घनसाली ब्लॉक और तहसील मुख्यालय होने के कारण दोनों स्थानों के बीच आवागमन लगातार बना रहता है। चारधाम यात्रा सीजन के दौरान मई से जुलाई तक बसों और जीप-टैक्सियों की कमी के कारण स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शहरी विकास विभाग की ओर से नगर पंचायत को दो नए कूड़ा वाहन भी जल्द मिलने वाले हैं। वर्तमान में उपलब्ध कूड़ा वाहन पुराने हो चुके हैं और बार-बार खराब होने से कूड़ा उठान प्रभावित होता है। नए वाहनों के आने से कूड़ा निस्तारण व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। वार्ड नंबर छह में 1.24 करोड़ रुपये की लागत से रजत जयंती पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है। पार्क में बच्चों के लिए झूले, चरखी और अन्य खेल उपकरण लगाए जाएंगे। बुजुर्गों के बैठने के लिए चेयर व विश्राम की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अध्यक्ष राणा ने कहा कि नगर पंचायत का प्रयास है कि क्षेत्रवासियों को बुनियादी सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएं। अन्य विकास योजनाओं पर भी काम तेजी से किया जाएगा।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनकर तैयार, सेवाओं के लिए 31 मार्च तक का इंतजार

नई टिहरी संवाददाता. जौनपुर ब्लॉक के श्रीकोट क्षेत्र के लोगों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (उप स्वास्थ्य केंद्र) की सेवाएं शुरू होने के लिए अब 31 मार्च तक इंतजार करना पड़ सकता है। निर्माणाधीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भवन निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने भवन को हैंडओवर लेने का काम शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने पहले दिसंबर से केंद्र का संचालन करने की बात कही थी लेकिन पानी और बिजली का कनेक्शन लेने की प्रक्रिया तय समय पर कार्य पूरा न होने से लोकार्पण की तिथि भी पीछे खिसकती जा रही है। श्रीकोट में उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। वर्ष 2020 में सरकार ने केंद्र के लिए 42.47 लाख रुपये की स्वीकृति दी थी लेकिन भूमि के अभाव में यह प्रोजेक्ट अटका हुआ था। गत वर्ष श्रीकोट गांव निवासी रणवीर सिंह बिष्ट ने स्वास्थ्य विभाग को अपनी दो नाली भूमि दान देकर इस कार्य को गति दी थी। कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग के जेई पंकज राणा ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण अब पूरा हो चुका है। बिजली का कनेक्शन लेने के लिए विभाग ने आवेदन किया है। इस माह के अंत तक भवन स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर कर दिया जाएगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का संचालन शुरू होने से श्रीकोट, कोट, भटवाड़ी, बिटौसी, घियाकोटी, संदुल, झिंगरी, घराणा, एंदा गांव के लोगों इसका लाभ मिलेगा। अब तक श्रीकोट क्षेत्र के लोगों को बुखार, सिरदर्द की दवाई लेने के लिए भी 30 किमी दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नैनवाग का रुख करना पड़ता है। उप स्वास्थ्य केंद्रों को सरकार ने अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम दिया है। श्रीकोट में भवन तैयार हो चुका है। भवन को हैंडओवर लेने की प्रक्रिया चल रही है। 31 मार्च से पहले भवन का लोकार्पण करने की तैयारी की जा रही है। - डॉ. श्याम विजय, सीएमओ टिहरी

भंग्यूल में शराब पीने-पिलाने पर 21000 रुपये जुर्माना

चमोली संवाददाता. विकासखंड के भंग्यूल गांव में ग्रामीणों ने सार्वजनिक बैठक आयोजित कर गांव में शराब पीने-पिलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ग्राम प्रधान मिथलेश फरस्वाण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि गांव में किसी भी सार्वजनिक कार्य में शराब पीने व पिलाने पर संबंधित परिवार से 21000 रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा। महिला मंगल दल की महिलाओं द्वारा गांव में शराब के विरुद्ध निगरानी रखी जाएगी। गांव में माह में एक बार स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस मौके पर महिला मंगल दल अध्यक्ष पार्वती देवी, प्रकाश सिंह राणा, अमर सिंह, पंकज, राजेंद्र सिंह, भगत सिंह, कुंदन शाह, महेंद्र सिंह, विनोद राणा, कमलेश बिष्ट आदि मौजूद रहे।

खूब हुआ प्रचार-प्रसार, अधिकारी नहीं पहुंचे जनता के द्वार

चमोली संवाददाता. तलवाड़ी में बुधवार को आयोजित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के लिए खूब प्रचार-प्रसार किया गया लेकिन सचिव एवं निदेशक शहरी विकास विभाग विनोद गिरी गोस्वामी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इससे के नहीं पहुंचने से जनता नाराज नजर आई। गोस्वामी ने नहीं आने से खानापूत बने इस शिविर का संचालन प्रभारी बीडीओ देवाल जयदीप बेलवाल ने किया और ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं दर्ज करवाईं। तलवाड़ी पंचायत घर में बुधवार को अपर सचिव एवं निदेशक शहरी विकास विभाग विनोद गिरी गोस्वामी की अध्यक्षता व अन्य सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी की मौजूदगी में शिविर प्रस्तावित था। वहीं, बुधवार को नामित अधिकारी के शिविर में नहीं आने से जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित नहीं हुए। इस कारण जनता में नाराजगी देखने को मिली हो गई स्थिति को संभालते हुए देवाल के प्रभारी खंड विकास अधिकारी ने शिविर की अध्यक्षता की। इसमें लोगों ने जंगली जानवरों से खेती की सुरक्षा, माल्टा, कीवी, नाशपाती और आलू के विपणन की समस्या, इंटर कॉलेज तलवाड़ी तक सड़क का डामरीकरण करने, महाविद्यालय तलवाड़ी के अधूरे भवन का निर्माण करने तलवाड़ी स्टेट की कृषि भूमि पर तारबाड़ करने की मांग की। इस मौके पर लॉनिवि थराली के ईई रमेश चंद्र, एई बबीता, अवर अभियंता श्रीजय कुमार, डीएस भंडारी, सिंचाई विभाग के एई सिकंदर सिंह, जल निगम से कैलाश नैटियाल, मनोज सिंह गुसाई, सुनील पुरोहित, ग्राम प्रधान दीपा फरस्वाण, गोपाल सिंह, मंजू गाड़िया, भावना देवी आदि मौजूद थीं।

वनाग्नि रोकथाम के लिए सभी इकाइयां सक्रिय करें वन विभाग

नई टिहरी संवाददाता. वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक लेते हुए डीएम नितिका खंडेलवाल ने वनाग्नि रोकथाम के लिए लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग को सभी वन पंचायतों और वनाग्नि प्रबंध समितियों को सक्रिय कर ग्राम प्रभुत्वों से भी सहयोग लेने को कहा गया है। कलेक्ट्रेट में आयोजित वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम ने डीपीआरओ से कहा कि गर्मियों में जंगलों को आग से बचाने में सहयोग के लिए प्रधानाणियों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी करें। डीएफओ टिहरी पुनीत तोमर ने बताया कि वनाग्नि की रोकथाम के लिए डाइजर में कंट्रोल रूम के अलावा जगह-जगह 53 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। टिहरी वन प्रभाग में 40 वनाग्नि प्रबंध समितियां सक्रिय की गई हैं। बैठक में सीडीओ वरुणा अग्रवाल, डीएफओ नरेंद्रनगर दिगत नायक, डीएफओ टिहरी डैम सदीपा, एसडीएम स्नेहिल कुंवर, एसडीएम घनसाली अलकेश नौडियाल, एसडीओ जन्मेजय रमोला और सदीप सिंह चौहान आदि मौजूद थे।

पूर्व मंत्री धनाई ने ग्रामीणों को समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा

नई टिहरी संवाददाता. ब्लॉक के ग्राम पंचायत आरकोट और गुनोगी पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनाई ने ग्रामीणों से संवाद कर समस्याएं सुनीं। उन्होंने ग्रामीणों को समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिया। पूर्व मंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में कई योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया था जिसमें मुख्य सुरकंडा रोपवे, सुरकंडा पेयजल, क्षेत्र के लिए पर्यटन योजनाएं शामिल हैं। सुरकंडा रोपवे संचालित होने से मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में अच्छा इजाफा हुआ है। पर्यटन योजना के तहत सौंड-काणाताल क्षेत्र में होमस्टे योजना को स्वीकृत करवाकर सैकड़ों युवा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़े हैं। इस मौके पर ज्येष्ठ प्रमुख संजय मैठाणी, देव सिंह पुंडीर, बलवीर पुंडीर, संजय रावत, कृष्णा मंगगाई, रामेश्वरी देवी, विनीत पुंडीर, सुमित रावत मौजूद थे।

थराली के रतागांव में शराब के प्रचलन पर महिलाओं ने लगाई रोक

चमोली संवाददाता. थराली विकासखंड के रतागांव में महिलाओं ने बैठक कर शराब के प्रचलन पर रोक लगाने का निर्णय लिया। साथ ही गांव में रैली निकालकर शराब के नुकसान, नशे से दूर रहने के लिए जागरूकता रैली भी निकाली। कहा कि यदि कहीं शराब परोसी गई तो 10 से 21 हजार तक का जुर्माना लिया जाएगा। रतागांव में ग्राम प्रधान दीपा देवी, महिला मंगल दल अध्यक्ष रेखा देवी और निर्वतमान महिला मंगल दल अध्यक्ष खिलेश्वरी देवी के नेतृत्व में आयोजित हुई बैठक में महिलाओं ने कहा कि गांवों में आयोजित होने वाले सामाजिक समारोहों में शराब के प्रचलन को प्रतिबंधित किया जाएगा। कहा गया कि सामाजिक कार्यों में शराब के प्रचलन से युवा पीढ़ी पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। यही नहीं गांव का सामाजिक ताना बाना, और पारिवारिक माहौल भी खराब हो रहा है। कई बार नशे की हालात विवाद का कारण भी बन रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप फर्स्वाण ने बताया कि महिलाओं ने शराब परोसने, बेचने आदि के मामले में पकड़े जाने पर 10 से 21 हजार का जुर्माना किए जाने का निर्णय लिया है। इस दौरान महिलाओं ने गांव में रतागांव सड़क पर जागरूकता रैली भी निकाली। ग्रामीणों ने महिलाओं के इस प्रयास की सराहना करते हुए समर्थन दिया।

डीएम ने किया पोखरी एसडीएम कार्यालय और बीडीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण

चमोली संवाददाता. जिलाधिकारी गौरव कुमार ने पोखरी एसडीएम कार्यालय और खंड विकास कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कार्यालय में कर्मचारी कार्यों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए जिस पर डीएम ने बीडीओ को कड़ी फटकार लगाई। जिलाधिकारी मंगलवार को किमोटा में आयोजित शिविर के बाद एसडीएम कार्यालय पोखरी और बीडीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। एसडीएम कार्यालय में व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलीं। वहीं, खंड विकास कार्यालय के कर्मचारी अपने-अपने पटलों से संबंधित कार्यों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर डीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए बीडीओ को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने व्यवस्थाओं में सुधार लाते हुए शासकीय कार्यों को संपादित करने के निर्देश दिए। डीएम ने कार्यालय की कार्य प्रणाली, उपस्थिति, फाइलों के निस्तारण की स्थिति, न्यायालय में लॉबिंग वादों की समीक्षा की। डीएम ने उपजिलाधिकारी को निर्देश दिए कि तहसील परिसर में कर्मचारी आवास निर्माण, गैराज व अन्य निर्माण कार्यों के लिए भूमि का चयन कर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने राजस्व वसूली में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। डीएम ने अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि जनहित के मामलों का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निस्तारण करें। कार्यालयों में अनुशासन, समय पालन और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। इस दौरान एसडीएम अबरार अहमद, खंड विकास अधिकारी शिव सिंह भंडारी, तहसीलदार जितेंद्र रावत सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

महिलाओं से मंगलसूत्र लूट की सनसनीखेज वारदातों का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया

हल्द्वानी संवाददाता. /हल्द्वानी और रामनगर में महिलाओं से मंगलसूत्र लूट की सनसनीखेज वारदातों का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। करीब 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगलने और मैनुअल इंटेल्जेंस के दम पर पुलिस ने एक शांति हिस्ट्रीशीटर को दबोच लिया, जबकि उसका साथी अब भी फरार है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान फिरोज (36) पुत्र नंदराम, निवासी पदमपुर, थाना मिल्क खाना, जिला रामपुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी को खिलाफ रामपुर में हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मुकदमों दर्ज हैं। हल्द्वानी, मुखानी और रामनगर में भी उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ऐसे देते थे वारदात को अंजाम मुखानी थाना क्षेत्र की बीना पाठक, फतेहपुर की 75 वर्षीय कमला देवी और रामनगर की विजयलक्ष्मी, तीनों महिलाओं के गले से बाइक सवार बदमाशों ने मंगलसूत्र झपटे थे। आरोपी पहले सामान लेने या पता पूछने का बहाना बनाते और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते। एसएसपी



डी. मंजूनाथ टी.सी. के निर्देश पर गठित टीम ने घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए व्यापक जांच शुरू की। पुलिस को संदिग्ध बाइक प्लेट नं. 29 12 2325 के कालादूगी से हल्द्वानी आने की सूचना मिली। कालादूगी रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान एक आरोपी भाग निकला, जबकि फिरोज को मौके पर दबोच लिया गया। उसके कब्जे से दो पीली धातु के पेंडल बरामद किए गए हैं। पूछताछ में उसने तीनों घटनाओं को कबूल किया और बताया कि वह दोबारा वारदात की फिराक में हल्द्वानी आ रहा था। पुलिस का सख्त संदेश एसएसपी ने स्पष्ट किया कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। फरार आरोपी को गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशा दी जा रही है।

पूर्व सैनिक लाल सिंह रौतेला का सरयू घाट में परम्परागत धार्मिक रीति से अंतिम संस्कार

काण्डा/हल्द्वानी संवाददाता. बागेश्वर जिले के कमस्यार घाटी के नरगोली गांव निवासी पूर्व सैनिक लाल सिंह रौतेला का बुधवार को बागेश्वर में सरयू घाट में परम्परागत धार्मिक रीति से अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव देह को मुखानि बड़े पुत्र बिशन सिंह रौतेला और मंजुले बेटे दीपक सिंह रौतेला ने दी। वे लगभग 94 साल के थे। उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना के सिग्नल कोर से हवलदार के पद से सेवानिवृत्त लाल सिंह रौतेला का मंगलवार को हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। वे पिछले कुछ दिनों से उग्र संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे। एक हफ्ते से उनकी शारीरिक परेशानियां बढ़ गई थी। उनका मंजुला बेटा दीपक उन्हें घर नरगोली से बेरीनाग अस्पताल ले गया। जहां डॉक्टरों ने दवाइयां देकर उन्हें बेहतर इलाज के लिए हल्द्वानी ले जाने को कहा। हल्द्वानी ले जाने से पहले ही मंगलवार देर शाम को उन्हें हार्ट अटैक आया और वो अनन्त यात्रा पर चल दिए। पूर्व सैनिक लाल सिंह का जन्म 25 दिसम्बर 1933 को नरगोली गांव में गांवली देवी और रतन सिंह रौतेला की पांचवीं संतान के तौर पर हुआ। वे चार भाइयों व एक बहन में सबसे छोटे थे।



बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा से जुड़े बहुचर्चित मामले में नैनीताल हाईकोर्ट से राहत मिलने का सिलसिला जारी

हल्द्वानी संवाददाता. 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा से जुड़े बहुचर्चित मामले में नैनीताल हाईकोर्ट से राहत मिलने का सिलसिला जारी है। ताजा घटनाक्रम में न्यायालय ने तीन और आरोपियों को जमानत प्रदान की है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 85 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जमीन उलेमा-ए-हिंद (मौलाना अरशद मदन) की ओर से की जा रही कानूनी पैरवी के तहत जिया उर रहमान और रईस अहमद उर्फ दत्तु को अदालत से जमानत मिली है। संगठन की ओर से यह पैरवी मामले की शुरुआत से ही लगातार की जा रही है। जमीन उलेमा-ए-हिंद के नैनीताल जिलाध्यक्ष मौलाना मुकाम कासमी ने बताया कि संगठन प्रभावित लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि न्यायालय से लगातार सकारात्मक फैसले सामने आ रहे हैं और उम्मीद जताई कि शेष आरोपियों को भी आने वाले समय में राहत मिलेगी। उन्होंने आम लोगों से दुआ की अपील भी की। गौरतलब है कि बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जिनमें से कई अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की सुनवाई फिलहाल उच्च न्यायालय में जारी है और अलग-अलग याचिकाओं पर क्रमबद्ध तरीके से सुनवाई की जा रही है।

बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया

रामनगर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार प्रदेश में आम जनमानस को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने और जनसामान्य की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी ललित मोहन ख्याल की अध्यक्षता में बुधवार को पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में फरियादियों द्वारा बिजली, सड़क, पेयजल, पार्किंग, कूड़ा निस्तारण, अतिक्रमण, सिंचाई आदि से संबंधित 183 शिकायतें दर्ज कराई गईं जिसमें से



अधिकारिता समस्याओं का जिलाधिकारी द्वारा मौके पर ही निस्तारण कराया गया। प्रमुख समस्याओं में सभासद पारस गोला, राजीव अग्रवाल ने जिला विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की शिकायत की। जिस पर जिलाधिकारी ने प्राधिकरण के कर्मियों को हिदायत देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की समस्या प्राप्त होने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने प्राधिकरण को तहसील कार्यालय में ही कमरा तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिए। उन्होंने प्राधिकरण के कर्मियों को निर्देश दिए कि पुराने मकान के मरम्मत की केवल सूचना लें और इनफॉर्मेशन लिस्ट में अपडेट करें, कॉमर्शियल निर्माण कार्य हेतु सिंगल विंडो सिस्टम में आवेदन कराया जाए। उन्होंने कर्मियों की कार्यों की निगरानी एवं समस्याओं के निदान के लिए हर पंद्रह दिन में क्षेत्र का भ्रमण करने के निर्देश सचिव जिला विकास सेवा प्राधिकरण को दिए।

उन्मूलन एवं पुनर्वास केंद्र हीरानगर का औचक निरीक्षण किया



आया जिससे संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए। इस संबंध में गुरुवार 11 बजे तक समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। औचक निरीक्षण के दौरान यह भी आयुक्त के संज्ञान में आया कि उक्त हीरा नगर नशा मुक्ति केंद्र में केवल पुरुषों के लिए स्वीकृति दी है जबकि नशा मुक्ति केंद्र में महिला को रखा गया जिस पर आयुक्त ने गम्भीरता से लेते हुये नशा मुक्ति केंद्र के खिलाफ कार्यवाही के साथ ही स्पष्टीकरण के निर्देश मौके पर दिये। निरीक्षण के दौरान केंद्र में केवल 30 मरीजों के उपचार हेतु शासन स्तर से निशुल्क स्वीकृति प्रदान है लेकिन केंद्र में पंजिका के अनुसार 30 से अधिक लोगों का उपचार किया जाना पाया गया तथा उपस्थित रजिस्ट्रार में नाम दर्ज भी नहीं था।

झूठी सूचना देना एक युवक को भारी पड़ गया

हल्द्वानी संवाददाता. डायल 112 पर फायरिंग की झूठी सूचना देना एक युवक को भारी पड़ गया। मुखानी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए न सिर्फ उसकी पोल खोली, बल्कि पुलिस एक्ट के तहत 5 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूल लिया। मंगलवार रात 10:23 बजे तुषार कबड्वावल निवासी मल्ला फतेहपुर, ऊंचापुल थाना मुखानी ने डायल 112 पर कॉल कर दावा किया कि कुछ लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और फायरिंग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मुखानी सुशील जोशी ने बिना देर किए रात्रि अधिकारी उपनिरीक्षक सूरज सिंह व पीसीआर टीम को मौके पर रवाना किया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सच्चाई कुछ और ही निकली। वहां न कोई फायरिंग हुई थी और न ही हालात वैसे थे जैसा बताया गया। मामला केवल आपसी कहासुनी और मामूली झगड़े का निकला। झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश सामने आते ही कॉन्टर को थाने लाया गया। पुलिस ने तुषार कबड्वावल पुत्र देवेंद्र चंद्र निवासी मल्ला फतेहपुर, कटहरिया के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 5000 का चालान काट दिया।

युनाइटेड सैफी वैलफेयर एसो. हेतू शफाअत सैफी उधमसिंह नगर जिलाध्यक्ष मनोनित, बधाईयो का तांता

रामनगर (नैनीताल) संवाददाता. युनाइटेड सैफी वैलफेयर एसो. इण्डिया (रजि.) के उत्तराखंड प्रदेशाध्यक्ष मौ. उमर उर्फ बबू सैफी के द्वारा केलाखंडा



निवासी शफाअत हुसैन सैफी को उधमसिंह नगर का जिलाध्यक्ष मनोनित किया गया है। श्री सैफी के मनोनयन पर उन्हें बधाई देते हुये एसो. के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुल्तान अहमद सैफी के द्वारा उनसे देश की एकता अखण्डता व देशहित के लिये कार्य

तहसील परिसर रामनगर में विरोध प्रदर्शन किया

रामनगर संवाददाता. अधिवक्ताओं ने राजस्व विभाग से जुड़े मामलों में प्रक्रियागत समस्याओं को लेकर तहसील परिसर रामनगर में विरोध प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से कुमाऊँ मंडल कमिश्नर को भेजा है। बुधवार को भेजे गए ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल पहले जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन दे चुका था। समाधान दिवस के दौरान भी वार्ता का अनुरोध किया गया था। कोई प्रतिक्रिया न



मिलने पर अधिवक्ताओं ने धरना देकर अपनी बात रखी थी। कहा कि राज्य के राजस्व न्यायालयों में व्याप्त घोर अनियमितताओं के खिलाफ अधिवक्ताओं का आक्रोश खुलकर सामने आ गया। वार्दों में देरी, बहुत अधिक समय, धन व्यय, और वरिष्ठ अधिकारियों की उदासीनता के कारण आम जनता में राजस्व न्यायालयों के खिलाफ गहरा रोष पैदा हो रहा है। इन्हीं समस्याओं के विरोध में बुधवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत रामनगर बार एसोसिएशन और हल्द्वानी बार एसोसिएशन, साथ ही जिला बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्यों से पूर्ण अवकाश रखा। अधिवक्ताओं का आरोप है कि न्याय व्यवस्था में व्याप्त अव्यवस्थाओं के चलते आम जन को गैर-कानूनी व्यवसायिक व्यक्तियों की शरण में जाना पड़ रहा है, जिससे बाहुबली और धनी वर्ग के लोग, गरीब एवं सामान्य जनता का शोषण कर रहा है।

खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर चेकिंग अभियान चलाया गया

रामनगर संवाददाता. आयुक्त एवं अपर आयुक्त, खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर रामनगर के गूलरघाटी में आधा दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सरसों तेल एवं सोया रिफाईंड के खाद्य नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिया है। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि बुधवार को रामनगर में चेकिंग अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि त्यौहार में प्रयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री के 03 खाद्य नमूनों के सैम्पल लेकर लैब जांच के लिए भेज दिए गए ज्ञापन। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान स्वामियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री को विक्रय करने, बिना बिल के खरीद न करने और स्टॉक का विवरण रखने के विशेष निर्देश दिए। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया आगामी त्योहारों होली एवं रमजान को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है किसी भी सूरत में मिलावटी खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं होने दिया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त से सख्त कार्यवाही करेगा। आयुक्त के निर्देश पर जनपद में संयुक्त टीमों का गठन किया गया है जो प्रतिदिन कार्यवाही कर रही है जिसकी रिपोर्ट आयुक्त कार्यालय को भेजी जा रही है।



लकड़ी व्यवसायी रईस अहमद सैफी के आकस्मिक निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर

रामनगर संवाददाता. नगर के कांग्रेस नेता रहे व लकड़ी व्यवसायी रईस अहमद सैफी के आकस्मिक निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर छा गयी तथा गमगीन माहौल में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। मोहल्ला बम्बाघेर निवासी स्व सैफी के निधन पर नगर



पालिकाध्यक्ष हाजी मो अकरम, वसीम अकरम, अमन सैफी, लईक सैफी, राशिद गुड्डू, सैफी, डॉ जफर सैफी, जमील सैफी, मास्टर असगर सैफी, नसीम सैफी, नईम सैफी, पूर्व सभासद रुबीना सैफी, पार्शद सरफराज सैफी, सभासद पारस गोला, पूर्व सभासद अरिबती सिद्दार्थ, नावेद सैफी, निक्की अब्बासी, फैंजान अब्बासी, फरमान, अजीम फरीदी, यासीन सैफी, कदीर सैफी, गोरी सैफी, डॉ तनवीर अख्तर, डॉ नासिर सैफी, डॉ काशिफ सैफी, डॉ नदीम सैफी, रईस सिद्दीकी,

वाहिद ठेकेदार, साजिद जुल्फी, रियाजुल चांद बाबू, दानिश अंसारी, मोनु अंसारी, नफीस अंसारी, अतुल शर्मा आदि ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए मरहूम को मगफिरत के लिये दुआ की है।

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा

रामनगर संवाददाता. जिम कॉर्बेट नेचर गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद बुधानी के नेतृत्व में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया। दिए गए ज्ञापन में टाइगर रिजर्व के कोर हेविटेट में पर्यटन गतिविधियों के दौरान मोबाइल फोन उपयोग के



संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार विभागीय निर्देश जारी करने की मांग की गई। एसोसिएशन ने यह भी स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि उक्त आदेश केवल कोर एरिया तक सीमित है या बफर एरिया में भी लागू होता है, क्योंकि निर्णय में बफर क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ज्ञापन में यह मांग रखी गई कि पर्यटकों के मोबाइल फोन एवं लॉकर की चाबी को जिम्मेदारी नेचर गाइड और वाहन चालक पर न डाली जाए। इसकी व्यवस्था विभागीय स्तर पर सुनिश्चित की जाए। एसोसिएशन ने कहा कि नेचर गाइड विभाग की "आंख और कान" के रूप में कार्य करते हैं और जंगल में अवैध गतिविधियों की सूचना देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि भविष्य में गाइडों के मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो विभाग द्वारा सभी गाइडों को कैमरा एवं वायरलेस सेट उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। साथ ही सभी सफारी गेटों पर विभागीय चेकिंग व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग भी की गई, ताकि कोई भी पर्यटक वर्जित सामग्री के साथ सफारी क्षेत्र में प्रवेश न कर सके। एसोसिएशन ने आशा व्यक्त की है कि पार्क प्रशासन शीघ्र ही इस विषय में स्पष्ट आदेश जारी करेगा, जिससे न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन हो सके। क्षेत्रीय रोजगार, सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित रह सके। इस दौरान ज्ञापन देने वालों से अनिल चौधरी, कैलाश पापने, राजेश नेगी, हरि शंकर देव, नीरज, चंदन, योगेश, उर्मिला, प्रीति, पवन आदि मौजूद रहे।

मोहम्मद शाहरुख सैफी को आजाद समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष बनाया

रामनगर संवाददाता. आजाद समाज पार्टी ने रामनगर निवासी मोहम्मद शाहरुख सैफी को आजाद समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। आजाद समाज पार्टी के कुमाऊँ मंडल प्रभारी लेखराज गौतम ने आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर मोहम्मद शाहरुख सैफी को आजाद समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। शाहरुख सैफी ने कहा कि वह पार्टी को मजबूत बनाने और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ा जाएगा।



शालिनी पांडे और जहान कपूर की कॉमेडी सीरीज बैंडवाले की रिलीज तारीख जारी



विजय देवरकोंडा के साथ अर्जुन रेड्डी से लोकप्रियता हासिल करने वाली अभिनेत्री शालिनी पांडे अपनी नई वेब सीरीज को लेकर चर्चा में आ गई हैं। उनकी इस म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज का नाम बैंडवाले है, जिसे अक्षय वर्मा और अंकुर तिवारी ने निर्देशित किया है। ब्लैक वॉरेंट वाले जहान कपूर भी सीरीज का हिस्सा हैं, जो दिवंगत अभिनेता शशि कपूर के पोते हैं। ओएमएल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बैंडवाले का प्रीमियर भारत सहित 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में होगा। बैंडवाले अमेजन प्राइम वीडियो की ओरिजनल सीरीज है। इसकी कहानी एक युवा कवयित्री मरियम (शालिनी) के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी स्वतंत्रता और आत्म-पहचान की तलाश में गुमनाम रूप से अपनी कविताओं को ऑनलाइन साझा करती है। उसकी जर्नी में उसका साथ रोबो और डीजे साइको देते हैं, जो उसके साथी और सबसे करीबी दोस्त हैं। सीरीज में जाने-माने कंपोजर यशराज मुखाते का संगीत भी शामिल है, जिससे कहानी की भावनात्मक यात्रा को आकार मिलता है। बैंडवाले वैलेंटाइन से एक दिन पहले, यानी 13 फरवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक देने के लिए तैयार है। इसमें शालिनी और जहान के अलावा खानंद किरकिरे, सजना दीपू, आशीष विद्यार्थी और अनुपमा कुमार सहित अन्य सितारे भी शामिल हैं। बता दें, शालिनी को आखिरी बार फिल्म राहु केलु में देखा गया था जो 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसमें पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा मुख्य किरदार में थे।

बॉर्डर 2 के कहर के आगे बेखौफ हुई मर्दानी 3, दूसरे संडे धुआंधार छापे करोड़ों

रानी मुखर्जी ने 30 जनवरी, 2026 को शर्मदानी 3 के साथ बड़े पर्दे पर अपना लॉन्ग अवैटेड कमबैक किया था। फिल्म में पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी राय के अपने पॉपुलर किरदार में रानी ने एक बार फिर एक दमदार, सामाजिक थ्रिलर से धमाल मचा दिया है। फिल्म ने पहले हफ्ते में ठीक कमाई की थी और दूसरे वीकेंड पर तो इसने जबरदस्त तेजी दिखाते हुए खूब नोट बटोर लिए। चलिए यहां जानते हैं शर्मदानी 3 ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे संडे को कितना कलेक्शन किया है? रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म शर्मदानी 3 बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई कर रही है। बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की वॉर ड्रामा शर्बॉर्डर 2 से कड़ी टक्कर का सामना करने के बावजूद, इस कॉपी ड्रामा ने दूसरे वीकेंड पर धमाल मचा दिया है। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनलक की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने दूसरे संडे को यानी रिलीज के 10वें दिन 4 करोड़ रुपये कमाए हैं। यह बढ़ोतरी, हालांकि मामूली है, लेकिन यह बताता है कि फिल्म को वीकेंड और छुट्टी का फायदा मिला। वहीं 9वें दिन (दूसरे शनिवार) को फिल्म ने लगभग 3.5 करोड़ रुपये कमाए, जो हफ्ते के दिनों के आंकड़ों की तुलना में एक अच्छी बढ़ोतरी है। इससे पहले, शर्मदानी 3 ने गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन 1.85 करोड़ रुपये कमाए थे। 10वें दिन 4 करोड़ रुपये के कलेक्शन को मिलाकर, फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब लगभग 35.65 करोड़ रुपये हो गया है। शर्मदानी 3 को सिनेमाघरों में कड़ी टक्कर मिल रही है। सनी देओल और वरुण धवन की वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 अभी भी आम दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है, जबकि संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की वध 2 जैसी नई रिलीज भी दर्शकों को खींच रही हैं। इस भीड़भाड़ वाले रिलीज विंडो ने शर्मदानी 3 की दूसरे हफ्ते में ग्रोथ को उम्मीद को कम कर दिया है। हालांकि अच्छी वर्ड ऑफ माउथ और रानी मुखर्जी की स्टार पावर फिल्म को बनाए रखने में मदद कर सकती है, भले ही कलेक्शन में तेजी से उछाल आने की संभावना कम हो।

धनश्री वर्मा का गहरे हरे गाउन में ग्लैमरस लुक हुआ वायरल, तस्वीरें देख फैंस बोले- स्टनिंग ब्यूटी

धनश्री वर्मा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर किया है। उनका ये नया फोटोशूट उनके फैंशन सेंस और ग्लैमरस अंदाज का बेहतरीन उदाहरण है। गहरे हरे रंग की गाउन जो शॉर्ट फ्रंट और लंबी ट्रेन के साथ डिजाइन की गई है उनके लुक को रॉयल टच दे रही है। गाउन का फिट और फैब्रिक उनके शरीर पर परफेक्ट बैठ रहा है जिससे उनका स्टाइल और भी निखर कर सामने आ रहा है। धनश्री वर्मा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ बेहद स्टाइलिश और स्टनिंग तस्वीरें शेयर की हैं।

इस फोटोशूट में उनका लुक ऐसा है कि देखते ही बन रही है। उन्होंने गहरे हरे रंग की गाउन पहनी है जो शॉर्ट फ्रंट और लंबी ट्रेन के साथ डिजाइन की गई है। गाउन का कट और फैब्रिक उनकी फिगर पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है और ये उनके लुक में ग्लैमरस टच जोड़ रहा है। फोल्डेड ट्रेन और डिजाइन उन्हें रॉयल और एलीगेंट लुक दे रहे हैं जो हर नजर को अपनी ओर खींच रहे हैं। धनश्री के बाल सॉफ्ट वेवी स्टाइल में सेट किए गए हैं जिससे उनका चेहरा और भी निखर कर सामने आ रहा है। मेकअप भी बहुत ही सिंपल है। उन्होंने हल्की स्मॉकी आईज, सटल लिप कलर और चेहरे पर नैचुरल ग्लो उनके लुक को पूरा कर रहे हैं। शाइनिंग होल्स उनके आउटफिट के साथ परफेक्ट मैच कर रही हैं। फोटोशूट में उनकी पोजिंग भी कमाल की है। धनश्री ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, चमकों की दुनिया में कोमल कृपा। इस कैप्शन के साथ फैंस ने भी उन पर खूब प्यार लुटाया है। कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं कि वह बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। स्टनिंग ब्यूटी और उनकी ब्यूटी का क्या ही कहना है। उनके फैंस के प्यार और तारीफों ने इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर और भी वायरल बना दिया है।



अपने किरदार को जीने लगी हूं, ड्रैगन का किरदार निभाने वाली कनिका मान ने खोले किरदार से जुड़े राज



टीवी के पॉपुलर सीरियल गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा की कनिका मान एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार वह आम इंसान बनकर नहीं, बल्कि ड्रैगन बनकर फैंस का दिल जीतने वाली हैं। अब नागिन 7 में अपनी एंट्री और ड्रैगन के किरदार पर कनिका मान ने कहा कि ड्रैगन का किरदार निभाना उनके लिए सपने जैसा है। कनिका मान ने अपने ड्रैगन के खूंखार किरदार पर बात करते हुए कहा, सीरियल में बीते 12 एपिसोड से ड्रैगन दिखाया जा रहा है और दर्शक पहले से ही उससे कनेक्टेड हैं। लेकिन बस अब नया चेहरा मेरा होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि मैं ड्रैगन का किरदार अच्छे से निभा पाऊंगी। ड्रैगन की दुनिया अलग है, लेकिन ड्रैगन बनने से पहले किरदार राधिका के जीवन में कई उतार-चढ़ाव हैं, जो दर्शकों को कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। मुझे ड्रैगन के लुक को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है।

देहरादून में आयोजित शी फॉर स्टेम उत्तराखण्ड विषय पर आयोजित कार्याशाला में पहुंचे सीएम धामी

देहरादून संवाददाता. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के अवसर पर उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, सुढ़ोवाला (प्रेमनगर, देहरादून) में आयोजित 'शी फॉर स्टेम उत्तराखण्ड' विषयक कार्याशाला में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने 'अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस' के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं तथा कार्याशाला में उपस्थित सभी महानुभावों का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने 'शी फॉर स्टेम' विशिष्ट कार्यक्रम के माध्यम प्रदेश की 20 प्रतिभाशाली बेटियों को 50-50 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि शी फॉर स्टेम के तहत हर जनपद में पांच छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जिसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि स्टेम हेतु स्टार्टअप आरंभ करने के लिए में छात्राओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। महिला प्रौद्योगिकी केंद्रों में स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस कार्यक्रम के माध्यम से होनहार बेटियों को ज्ज्व अर्थात साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्रों में शिक्षा एवं करियर के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही दूरस्थ एवं सीमांत क्षेत्रों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने तथा महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए इन-मोवी, विज्ञानशाला इंटरनेशनल, यूक्रॉस्ट तथा उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सहित सभी आयोजकों को साधुवाद देते हुए कहा कि उन्होंने इस दूरदर्शी पहल को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय इतिहास साक्षी है कि नारीशक्ति केवल सामाजिक या पारिवारिक जीवन तक सीमित नहीं रही, बल्कि विज्ञान,



मुख्यमंत्री की घोषणा

- शी फॉर स्टेम के तहत हर जनपद में पांच छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी
- स्टेम हेतु स्टार्टअप आरंभ करने के लिए में छात्राओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे
- महिला प्रौद्योगिकी केंद्रों में स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जाएगा
- उत्तराखंड में मातृशक्ति के उत्थान को समर्पित धामी सरकार
- प्रदेश में 1.67 लाख से अधिक महिलाएं बनी लक्ष्यपति दीवी
- ड्राप आउट छात्राओं को शिक्षा से जोड़ रही धामी सरकार
- 'शी फॉर स्टेम' कार्याशाला में सीएम धामी ने 20 छात्राओं को वी 50-50 हजार की छात्रवृत्ति
- ज्ज्व में 42-43% छात्राओं की भागीदारी भारत की ताकत: सीएम धामी
- राज्य में पहली विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति लागू
- देहरादून में बन रही देश की पांचवां साइंस सिटी
- डिजिटल इंडिया से बेटियों को मिल रहा तकनीकी सशक्तिकरण
- तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक 'श्रु नारी सशक्तिकरण से होगा संकल्प साकार

दर्शन, खगोलशास्त्र एवं चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में भी अग्रणी रही है। वैदिक काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों दार्शनिक विमर्श में अग्रणी थीं, जबकि लीलावती ने गणित के क्षेत्र में विश्व को दिशा प्रदान की। उन्होंने उल्लेख किया कि चरक-संहिता और सुश्रुत-संहिता जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथों के विकास में भी स्त्रियों के योगदान के प्रमाण मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक काल में भी अनेक महिलाओं ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण योगदान देकर देश का गौरव बढ़ाया है। स्वतंत्रता से पूर्व के समय में, जब महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना भी चुनौतीपूर्ण था, अन्ना मणि ने भारत की पहली महिला मौसम वैज्ञानिक बनकर इतिहास रचा और 'वेदर वुमन ऑफ

इंडिया' के रूप में प्रसिद्ध हुईं। उन्होंने मौसम विज्ञान और वैज्ञानिक उपकरणों के विकास में अमूल्य योगदान दिया। इसी प्रकार कमला सोहोनी विज्ञान के क्षेत्र में पीएचडी प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला बर्नी और यह सिद्ध किया कि प्रतिभा किसी बंधन की मोहताज नहीं होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान भारत में डॉ. टेसी थॉमस, जिन्हें 'मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया' कहा जाता है, ने अगिन-4 और अगिन-5 जैसी महत्वपूर्ण मिसाइल परियोजनाओं का नेतृत्व कर देश की सामरिक शक्ति को नई ऊँचाइयों दी हैं। साथ ही 'रॉकेट वुमन' के नाम से प्रसिद्ध डॉ. ऋतु करिधल ने मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर भारत को वैश्विक मंच पर गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री ने

कहा कि इन सभी महान विभूतियों का जीवन यह संदेश देता है कि जब नारी को अवसर मिलता है तो वह न केवल अपने लिए मार्ग बनाती है, बल्कि पूरे राष्ट्र को नई दिशा देने का सामर्थ्य रखती है। उन्होंने कहा कि यह संयोग नहीं है कि आज भारत में ज्ज्व क्षेत्रों से स्नातक होने वाले विद्यार्थियों में लगभग 42ख43 प्रतिशत छात्राएँ हैं, जो कई विकसित देशों की तुलना में अधिक है। यह आँकड़ा इस बात का प्रमाण है कि भारत की बेटियाँ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित के क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं तथा नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अब आवश्यकता इस बात की है कि बेटियों को अवसर, संसाधन और विश्वास देकर उनके सपनों को उड़ान दी जाए, ताकि वे अपने भविष्य के साथ-साथ विकसित भारत के संकल्प को भी साकार करने में योगदान दे सकें।

सीएम धामी ने कहा कि प्रथममंत्री का स्पष्ट मत है कि इकोसर्वी सदी में भारत की प्रगति विज्ञान और तकनीकी नवाचार पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व ऊँचाइयाँ प्राप्त की हैं। कोरोना वैक्सिन निर्माण, चंद्रयान-3, आदित्य स और गगनयान मिशन जैसी उपलब्धियों ने देश को नए कीर्तिमान स्थापित करने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत वैश्विक तकनीकी क्रांति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री का मानना है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी आधुनिक आबादी तकनीकी रूप से कितनी सक्षम है और नवाचार के क्षेत्र में कितना योगदान दे रही है।

उत्तराखंड में बदलेगा मौसम.. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना

देहरादून संवाददाता. उत्तराखंड के मौसम में अगले कुछ दिनों के दौरान फिर बदलाव आने वाला है। दो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। आने वाले दिनों में पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। हालांकि इन पश्चिमी विक्षोभों के कमजोर रहने के कारण मैदानी इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। सुबह और रात के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। 16 फरवरी को बारिश/बर्फबारी: मौसम विभाग ने 13 और 16 फरवरी को बैक-टू-बैक 2 नए पश्चिमी विक्षोभ के ऐक्टिव होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इसके प्रभाव से 16 फरवरी से उत्तराखंड में मौसम बदलने का पूर्वानुमान जारी किया है।

कुंभ 2027 के सभी स्थायी कार्य समय पर होंगे पूरे, गुणवत्ता की जांच आईआईटी रुड़की करेगा: सोनिका

हरिद्वार संवाददाता. कुंभ मेलाधिकारी सोनिका ने कहा कि कुंभ मेला 2027 से जुड़े सभी स्थायी प्रकृतिक कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी जांच कराई जाएगी। इनमें आईआईटी रुड़की और अन्य मान्यता प्राप्त एंजिनीयर्स शामिल होंगे। यह बात उन्होंने प्रेस क्लब में आयोजित संवाद कार्यक्रम में कही। सोनिका ने बताया कि कुंभ मेला से संबंधित विभिन्न विकास कार्य लगभग 1224 करोड़ रुपये की लागत से होंगे। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाएँ तय समय सीमा में पूरी कर ली जाएंगी। मेला क्षेत्र के सभी 32 सेक्टरों को व्यवस्थित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए योजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने बताया कि कुंभ 2027 की तैयारियों के तहत करीब 220 करोड़ रुपये की लागत से सीवर लाइन, सड़क निर्माण, पुलों के निर्माण और नए घाटों के विकास के कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त बहुउद्देश्यीय सीसीआर-2 परियोजना को शासन से स्वीकृति मिलते ही उसका निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। पत्रकारों के सवाल पर सोनिका ने कहा कि रिकॉर्ड समय में इतने व्यापक कार्यों को पूरा करना चुनौती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मेला अधिष्ठान में लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के अलग-अलग खंड स्थापित हैं।